

जलवायु परिवर्तन - जल, जीवन और जागरूकता

अनिल कुमार लोहनी

वैज्ञानिक ई-1, राजसं., रुड़की

मनुष्य इस धरती पर ईश्वर की श्रेष्ठतम रचनाओं में से एक है। प्रकृति में व्याप्त समस्त जीवों की तुलना में मनुष्य को ज्ञान का अतुलित भंडार मिला है। इस ज्ञान का उपयोग कर मनुष्य ने प्राचीनतम पाषाण युग से आज के औद्योगिक युग तक की यात्रा कर पृथ्वी पर वह सब साधन जुटा लिये हैं, जो कि शायद कभी कल्पना से परे थे। किन्तु इस प्रगति के लिये मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन करना प्रारम्भ कर दिया। प्रकृति एवं पर्यावरण पर मनुष्य ने इतना अधिक हस्तक्षेप किया है कि पर्यावरण का रूप दिन प्रतिदिन भयावह होता गया है। अपने स्वार्थ के लिये मनुष्य ने प्रकृति के संतुलन को इतना अधिक बिगाड़ दिया है कि इसका सीधा प्रभाव जलवायु परिवर्तन के रूप में देखा जा सकता है। यदि मनुष्य ने समय रहते जलवायु परिवर्तन के कारणों का निवारण नहीं किया तो कहीं ऐसा न हो कि इस धारा से जीवन ही लुप्त हो जाये। मानव समाज पर मंउराते इस खतरे को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर में निर्विवाद रूप से, जलवायु परिवर्तन को वर्तमान समय की सबसे प्रमुख समस्या के रूप में देखा जा रहा है। पर्यावरणविदों तथा विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े वैज्ञानिकों के समक्ष जलवायु परिवर्तन तथा विभिन्न क्षेत्रों में इसके प्रभाव का आकलन सबसे बड़ी चुनौती है। जलवायु परिवर्तन की यह चुनौती, आजीविका के लिये संघर्षरत सामान्य मनुष्य के लिये जहाँ एक चर्चा का विषय मात्र है वहीं वास्तविकता यही है कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी पर विद्यमान सभी जीवों का जीवन इससे प्रभावित होता है। इसी कारण दुनिया के अधिकांश देश उन कारणों को गंभ्रता से लेने लगे हैं जो धरती के जलवायु परिवर्तन के मुख्य कारक हैं।

हमारे देश में भी जलवायु परिवर्तन की समस्या के कारणों के अध्ययन और निवारण के लिये विभिन्न कार्यक्रम संचालित किये गये हैं। वैसे तो जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में देखने को मिलता है किन्तु इस लेख में जलवायु परिवर्तन, जल और जनजीवन पर इसका मुख्य प्रभाव तथा आवश्यक जागरूकता अभियानों के विषय में चर्चा की गई है।

पृथ्वी के ताप कटिबन्ध क्षेत्र और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन के विषय में चर्चा करने से पूर्व यह जानलेना अतिआवश्यक है कि पृथ्वी पर अलग-अलग स्थानों की जलवायु, ताप, आर्द्रता तथा वर्षण एक दूसरे से भिन्न हैं। इसी कारण पृथ्वी को अनेक आधारों पर अलग-अलग क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है। औसत

वार्षिक तापमान के आधार पर मोटे-तौर पर पृथ्वी को पाँच क्षेत्रों में बाँटा गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में सूरज की किरणें कितनी लम्बवत गिरती हैं यह उस स्थान की भूमध्य रेखा से दूरी पर निर्भर करता है। इसी कारण पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों को उनकी भूमध्य रेखा से दूरी के अनुसार निम्नलिखित पाँच ताप कटिबन्ध क्षेत्रों में बाँटा गया है।

1. उत्तरी शीत कटिबन्ध यह उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के उत्तर का क्षेत्र है तथा उत्तरी ध्रुव इसके केन्द्र हैं।
2. उत्तरी शीतोष्ण कटिबन्ध यह क्षेत्र उत्तरी ध्रुवीय वृत्त और कर्क रेखा के बीच का क्षेत्र है।
3. उष्ण कटिबन्ध यह क्षेत्र कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है।
4. दक्षिणी शीतोष्ण कटिबन्ध यह क्षेत्र मकर रेखा और दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के बीच का क्षेत्र है।
5. दक्षिणी शीत कटिबन्ध यह क्षेत्र दक्षिणी ध्रुवीय वृत्त के दक्षिण का क्षेत्र है जिसेक केन्द्र में दक्षिण ध्रुव है।

जल, जंगल और जमीन, इन तीनों तत्वों के बिना प्रकृति अधूरी है। कहा जाता है कि इस पृथ्वी पर सबसे समृद्ध देश वहीं है जहाँ यह तीनों प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है जलवायु में परिवर्तन अपरिहार्य है तथा पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबन्ध क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन सीमित गति से लगातार जारी है। औद्योगिकीकरण और विकास की बढ़ती रफतार के कारण विभिन्न ताप कटिबन्ध क्षेत्रों में जो परिवर्तन देखने में आ रहे हैं उनसे इन क्षेत्रों के समुचे परिस्थितिक तंत्र पर कहर टूट पड़ा है। यही नहीं इस तीव्र परिवर्तन ने इन क्षेत्रों की जीवन शैली, समाज और समुदाय को झकझोर दिया है। हिंद महासागर में 1200 द्वीपों पर फैला मालदीप एक समय में उष्णकटिबंध क्षेत्र का स्वर्ग माना जाता था वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार यह सुंदर देश हो सकता है अगले पचास वर्षों में पूरी तरह जलमग्न हो जाये। उष्णकटिबंधीय वन वायुमंडल को आक्सीजन प्रदान करने के साथ-साथ जैव विविधता को भी सुरक्षित रखते हैं। जंगल ग्लोबल वार्मिंग का प्रभव कम करने में सहायक होते हैं किन्तु औद्योगिकीकरण के साथ ही जंगलों की कटाई से वायुमंडल को दो प्रकार से हानि पहुँचती है- 1. कार्बन डाईआक्साइड का आक्सीजन में बदलने वाले वृक्षों की संख्या घट जाती है। 2. लकड़ी को जलाने से उसमें विद्यमान कार्बन हवा में मिल जाता है।

जल संसाधन और जलवायु परिवर्तन

जल संसाधन जल के वह स्रोत हैं, जो मानव के लिये उपयोगी हो या जिनके उपयोग की संभवना हो। विभिन्न मानवीय उपयोगों जैसे घरेलू कार्य, कृषि, औद्योगिक मनोरंजन एवं पर्यावरण गतिविधियों के लिये ताजे पानी की आवश्यकता होती है। पृथ्वी के पानी का 97.5 प्रतिशत खारा है जबकि केवल 2.5 प्रतिशत ही मीठा जल है। पृथ्वी पर स्थित मीठे जल का

दो-तहहाई हिस्सा हिमानी और ध्रुवीय बर्फीली टोपी के रूप में जमा है तथा शेष पिघला हुआ पानी भूमि के अन्दर, ऊपर तथा हवा में है। जनसंख्या में आतपूर्व दर से वृद्धि एवं जलवायु परिवर्तन के कारण स्वच्छ पानी की पर्याप्तता लगातार कम हो रही है। सन् 2000 में दुनिया की आबादी 6.2 अरब थी। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार सन् 2050 तक जनसंख्या में 3 अरब की वृद्धि हो जायेगी। जनसंख्या वृद्धि के कारण जल तनाव से ग्रस्त विकासशील देशों में जल की मात्रा और बढ़ेगी। अनुमान लगाया जाता है कि पृथ्वी का 15 प्रतिशत जल घरेलू उद्देश्य के लिये उपयोग होता है तथा घरों की बुनियादी आवश्यकताओं के लिये प्रतिदिन प्रति व्यक्ति लगभग 50 लीटर की खपत है तथा इससे बगीचों के लिये इस्तेमाल पानी शामिल नहीं है।

मौसम और जल चक्र के बीच बहुत ही करीबी संबंधों के कारण जलवायु परिवर्तन जल संसाधनों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। दुनियाभर में हुए विभिन्न अध्ययनों में यह कहा गया है कि बढ़ते तापमान के कारण 1. वाष्पीकरण में वृद्धि होगी। 2. वर्षा में क्षेत्रीय विविधता होगी 3. ताजे पानी की आपूर्ति में वृद्धि होगी 4. सूखा एवं बाढ़ विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग मसय पर अक्सर हो सकते हैं। 5. पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी और तुषार पिघलाव की संभावना है। जर्मनी के बॉन में जारी एक रिपोर्ट “इन सर्च ऑफ शेल्टर मैपिंग द इफैक्ट्स आफ क्लाइमेट चेंज आन ह्यूमेन मिटिगेशन एण्ड डिसप्लेसमेंट” में कहा गया है कि ग्लेशियारों का पिघलना जारी है। इसके परिमस्वरूप पहले बाढ़ आयेगी और फिर लम्बे समय तक जल की आपूर्ति थम जाएगी।

हमारे देश का बहुत बड़ा क्षेत्र बाढ़ की विभीषिका को लगातार झेलता आ रहा है। परन्तु विगत कुछ वर्षों से बाढ़ के स्वरूप, प्रवृत्ति व आवृत्ति में होने वाले परिवर्तनों को जलवायु परिवर्तन के साथ जोड़कर देखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लिये बाढ़ कोई नई बात है परन्तु ऐसा माना जाने लगा है कि मौसम में हो रहे बदलाव ने इस प्राकृतिक प्रक्रिया की तीव्रता व स्वरूप को बदल दिया है। मौसम बदलाव का दूसरा प्रमुख प्रभाव सूखे के रूप में देखा जा सकता है। वैज्ञानिक अनुमानों के अनुसार तापमान में वृद्धि एवं वाष्पीकरण की दर तीव्र होने के परिणाम स्वरूप सूखाग्रस्त क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। यह भी अनुमान लगाया जा रहा है कि मौसम बदलाव के चलते वर्षा समयानुसार नहीं हो रही है और उसकी मात्रा में बदलाव आया है।

जलवायु परिवर्तन- शोध, कार्यक्रम एवं सम्मेलन

दुनिया के बढ़ते वैश्विक तापमान और जलवायु परिवर्तन के लिये कार्बन डाई आक्साइड को ही मुख्यतः जिम्मेदार माना जा रहा है। वास्तव में मानव की प्रत्येक गतिविधि के लिये

जीवाश्च ईधन जरूरी बन गया है । जीवाश्च ईधन के जलने की प्रक्रिया से उत्पन्न हाने वाली कार्बन डाईआक्साइड का स्तर वातावरण में लगातार बढ़ता जा रहा है बाकी की कसर तेजी से घटते जंगले ने पूरी कर दी है । कार्बनडाईआक्साइड में बढ़ोत्तरी से धरती से निकलने वाली गर्मी वातावरण से बाहर नहीं जा पा रही है **वेश्विक गर्माहट बढ़ते कार्बनडाईआक्साइड की मात्रा से चिंतित शिक्षित समाज ने कुछ नये शब्दों और विषयों को जन्म दिया जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, कार्बन ट्रेडिंग, कार्बन फुटप्रिंटस तथा जिओ इंजीनियरिंग इत्यादि ।** 1950 के दशक में जब ग्लोबल वार्मिंग जैसे शब्दों का प्रादुर्भाव नहीं हुआ था तथा वैज्ञानिक समाज **“न्यूकिलियर विंटर”** की बात करता था उस समय हवा में कार्बन डाई आक्साइड की मात्रा को एक शोध छात्र चार्ल्स कीलिंग ने मापा था । हवा में कार्बन डाई आक्साइड की सांद्रता को नापने वाला उपकरण बनाकर तथा विभिन्न प्रयोगों द्वारा कीलिंग ने निष्कर्ष निकाला कि वातावरण में कार्बन डाई आक्साइड की सांद्रता लगातार परिवर्तनशील है और इसका मुख्य कारण मानवीय गतिविधियां हैं । जलवायु परिवर्तन पर आज हो रही व्यापक एवं विभिन्न चर्चाएं कीलिंग के प्रयोगों पर आधारित हैं । परिणामस्वरूप, जिओ इंजीनियरिंग का अत्यधिक तेजी से प्रादुर्भाव एवं विकास हुआ है । जिओ इंजीनियरिंग द्वारा यह विचार किया जा रहा है कि ऐसी तकनीक का विकास किया जाए जिससे धरती पर पहुँचने वाली सौर विकिरण में कमी की जा सके । नोबल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक पॉल कर्टजन ने स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फर इंजेक्शन का सुझाव दिया जिसमें कि वातावरण की ऊपरी परत से सल्फर डाई आक्साइड को खुला छोड़ दिया जाता है । इस प्रक्रिया के दौरान यह बड़ी मात्रा में माइक्रोमीटर से छोटे सल्फेट के कणों में परिवर्तित हो जाती है। वातावरण में बिखरे सल्फेट के ये अनगिनत कण सौर विकिरण की फिर से अंतरिक्ष की ओर मोड़ देते हैं ।

जलवायु परिवर्तन पर हो रहे शोध के अतिरिक्त विभिन्न कार्यक्रम तथा सम्मेलन लगातार किये जा रहे हैं । बहुत सी पुस्तकें लिखी गईं तथा फिल्मों के माध्यम से जन जागृति लाने का प्रयास जारी है । इनमें से कुछ का वर्णन नीचे दिया गया है ।

- **“एन इनक्वैरिनिंग ट्रथ”** जलवायु परिवर्तन की भयावहता को दर्शाती इस फिल्म में अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अलगोर ने भूमिका निभाई थी ।
- **“स्टेट आफ फीयर”** माइकल क्रस्टन ने अपनी इस पुस्तक में जलवायु विज्ञान से संबंधित शोध कार्यों और उसमें सेलगन वैज्ञानिकों को जमकर आड़े हाथों लिया है ।
- **“लाइव अर्थ” संगीत कार्यक्रम** - अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति अलगोर के संगठन **“सेव अवरसेल्फस”** के तत्वाधान में 7 जुलाई, 2007 को यह संगीत कार्यक्रम पर्यावरण को लेकर जागृति पैदा करने के मकसद से किया गया ।

- “जलवायु परिवर्तन से सामना: अविभाजित विश्व में मानव एकता” राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम की इस रिपोर्ट में एक अध्याय है “खतरनाक जलवायु परिवर्तन से बचाव: असर को कम करने की रणनीति” इस अध्याय की शुरुआत गाँधी जी के एक उद्धरण से की गई है “अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तो रफतार बेमानी हो जाती है” ।
- “इन सर्च आफ शेल्टर मेटिंग इफेक्ट्स आफ क्लाइमेट चेंज आन ह्यूमेन मिटिगेशन एण्ड डिस्प्लेसमेंट” कोको वार्नर तथा एलेक्स सेरबिनि द्वारा तैयार इस रिपोर्ट में जलवायु संबंधी पलायन के बारे में चर्चा की गई है । यह रिपोर्ट विस्तार से जलवायु परिवर्तन के कारण स्थानीय वातावरण में हाने वाले बदलाव के कारण मनुष्यों का अधिक हरियाले वाले क्षेत्रों के पलायन के बारे में जानकारी देती है ।
- “लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट-2006” इस रिपोर्ट में कहा गया है कि विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों में प्रकृति को बेतहाशा दुहा है । हमने दोहन एवं दमन तो किया है किन्तु प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित करने की दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं किया ।
- इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आई पी सी सी) रिपोर्ट - आई पी सी सी ने 17 नवम्बर को स्पेन के वैलेशिया में जारी अपनी चौथी और अंतिम रिपोर्ट में कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि ग्लोबल वार्मिंग की क्षतिपूर्ति नहीं हो पाएगी । आई पी सी सी विभिन्न देशों के विशेषज्ञों और प्रतिनिधियों को मिलाकर बनाया गया साझा पैनल है जो संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से अपना काम इसके मौजूदा अध्यक्ष भारत के डा आर. के. पचौरी की अध्यक्षता में कर रहा है ।
- क्योटा प्रोटोकाल या संधि:- दिसम्बर, 1997 में जापान के क्योटा शहर में वार्ताओं का क्रम शुरू हुआ था । इसी वजह से इसे “ क्योटा संधि” नाम दिया गया है । रूस द्वारा नवम्बर, 2004 में अनुमोदन के बाद इसके क्रियान्वयन का रास्ता साफ हो गया और 16 फरवरी, 2005 से इसे लागू कर दिया गया । यह संधि विश्व के औद्योगिक देशों को 6 ग्रीनहाउस गैसों- कार्बन डाई आक्साइड, मीथेन, नइट्रस आक्साइड, सल्फर हेक्साफ्लोराइड, एच एफ सी तथा सी एफ सी में एक निश्चित सीमा तक कटौती करने को बाध्य करती है । इस संधि पर अमेरिका को छोड़ 184 देशों ने हस्ताक्षर किये हैं ।
- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणप कार्यक्रम (यू एन ई पी) ने सात अरब वृक्ष अभियान नाम से एक नई तथा अपेक्षाकृत अधिक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रारम्भ कर दिया है । जिसका लक्ष्य है कोपनहैगन सम्मेलन 2009 तक प्रत्येक व्यक्ति के लिये कम से कम एक वृक्ष लगाने का कार्यक्रम सम्पन्न करना ।
- “विश्व पर्यावरण दिवस 2009 का विषय है- आपके ग्रह को जरूरत है आप कि- जलवायु परिवर्तन से लड़ने को एव हों ” इस विषय के इस बात पर जोर दिया गया

है कि सभी देशों को जलवायु के संबंध में एक होने की जरूरत है । इस वर्ष के विश्वपर्यावरण दिवस का महमान देश मैक्सीको है । मैक्सीको का चयन इसलिए किया गया कि जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई में इसकी व्यावहारिक ओर सामाजिक भूमिका बढ़ती जा रही है ।

भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना (नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज)

प्रधानमंत्री मनमोन सिंह ने जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्ययोजना को जुलाई 2008 को पेश किया गया । कार्ययोजना को प्रधानमंत्री की सलाहकार समिति ने तैयार किया है । इसे प्रस्तुत करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा “जलवायु परिवर्तन आज एक वैश्विक चुनौती है इससे वैश्विक तालमेल और सहयोग से निपटा जा सकता है । अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में भारत अपनी भूमिका निभाने को तैयार है और अपना योगदान देना चाहता है” इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि किस तरह प्राकृतिक स्रोतों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करके पर्यावरण को प्रदूषणमुक्त बनाया जा सकता है ।

इस कार्ययोजना में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के बारे में कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि सरकार का मानना है कि भारत में ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन अन्य विकासशील देशों की तुलना में बहुत ज्यादा नहीं है । योजना में सभी राज्यों से कहा गया है कि विकास संबंधी पहले के बावजूद भारत की प्रति व्यक्ति ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की दर विकसित औद्योगिक देशों के प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से अधिक नहीं होगी ।

जलवायु में हो रहे बदलाव के मद्देनजर इस योजना का निर्माण किया गया है । योजना में 8 बातों को लागू करने की बात कही गयी है । यह योजनाएँ दीर्घकालिक और बहुदेश्य होंगी। इसके माध्यम से जलवायु में हो रहे बदलाव से निपटने की योजना है । इस योजना में जिस 8 बिन्दुओं पर बात की गयी है वे हैं -

1. ऊर्जा के कुल इस्तेमाल में सौर ऊर्जा के प्रयोग को बढ़ावा ।
2. ऊर्जा दक्षता के उपायों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना ।
3. जीवों के लिए अनुकूल पर्यावरण का निर्माण ।
4. पानी के सही इस्तेमाल के लिए प्रभाकारी रणनीति ।
5. हिमालय के ग्लेशियरों की सुरक्षा ।
6. पारिस्थितिक तंत्र को बढ़ाना ।
7. कृषि को जलवायु में तेजी से हो रहे बदलाव के अनुसार लचीला बनाना
8. इस क्षेत्र में शोध के लिए स्ट्रैटेजिक नॉलेज मिशन की स्थापना करना ।

इसी को ध्यान में रखकर केन्द्रीय जलसंसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के असर को लेकर इसके गहन अध्ययन का फैसला किया है, जिसमें वर्षा की घटती बढ़ती अवधि, नदियों के बदलते प्रभाव और ग्लेशियारों के पिघलने की गति पर नजर रखखी जायेगी। इसके लिए मंत्रालय ने एक विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है जिसमें केन्द्रीय जल आयोग, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड, केन्द्रीय भूजल बोर्ड व राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान को शामिल किया गया है। जल संसाधनों के अध्ययन में देश के जाने माने प्रमुख शिक्षण संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल किया जायेगा। मुख्यतः जिन संस्थानों को चिन्हित किया गया है उनमें आई आई टी, रूड़की, गुवाहाटी व खडकपुर के साथ एन आई टी, श्रीनगर पटना प्रमुख हैं। जल संसाधन मंत्रालय ने अध्ययन में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों पर अमल करने की बात कही है। दरअसल देश की बड़ी व मझली सिंचाई परियोजनाओं की समीक्षा की जायेगी। जलवायु परिवर्तन से इन योजनाओं की घटती क्षमता को बढ़ाने के उपायों पर भी विचार होगा। इसके लिए आई आई टी, केन्द्र व राज्य स्तरीय जल व भूमि शोध संस्थान अहम भूमिका निभायेंगे। बड़ी सिंचाई परियोजनाओं की संभावनाओं को खगांला जायेगा। जलसंसाधन मंत्रालय ने जल संसाधनों पर जलवायु परिवर्तन के अध्ययन को अपनी प्राथमिकता सूचि में सम्मिलित किया है।

जलवायु परिवर्तन पर जन जागरूकता

आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत है जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आम जनता को जागरूक करने की। दिनोदिन गंभ्र रूप लेती इस समस्या से निपटने के लिये आज आवश्यकता है एक ऐसे अभियान की जिसमें हम स्वप्रेरणा से सक्रिय भागीदारी निभायें। हम सब मिलकर इस अभियान में सहयोग दे सकते हैं जैसे कि:-

- ब्रुश से दातों की सफाई करते समय बहते पानी को रोक कर जल तथा ऊर्जा दोनों की बचत कर ऊर्जा उत्पादन के समय उत्सर्जित ग्रीन हाउस गैसों को कम कर सकते हैं। अतः जल संरक्षण एक प्राथमिकता होनी चाहिये।
- विद्युत चलित ट्रेड मिल का इस्तेमाल करने के बजाये पार्क में चहल कदमी कर ऊर्जा की बचत करें।
- घर के आसपास पौधा रोपण करें
- हर संभव तरीके से घर में बिजली की बचत करें तथा बिजली की जरूरतों को कम करना प्राथमिकता होनी चाहिये
- सार्वजनिक वाहनों का निजी वाहनो की तुलना में अधिक उपयोग करें।
- वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना चाहिये

इस प्रकार से अपने अनेक प्रयासों के द्वारा हम पृथ्वी को बचाने के अभियान में अपना योगदान दे सकते हैं। प्रकृति का रूप बदलने का सारा दोष मनुष्य के ऊपर ही जाता है अब यह मानव के हाथ में है कि वह किस प्रकार से अपनी बुद्धि और सूझबूझ का उपयोग कर अपनी इस भूल को सुधार ले। चूंकि जलवायु परिवर्तन किसी एक देश अथवा क्षेत्र तक सीमित नहीं है इसलिए इसमें कभी लाने हेतु सभी स्तरों पर ठोस उपायों की जरूरत है। अन्त में आई पी सी सी के अध्यक्ष डा. आर.के. पचौरी का यह बयान महत्वपूर्ण है जो उन्होंने अन्तिम रिपोर्ट जारी करते हुए व्यक्त किया था **“हमें अब उन मूल्यों या नैतिकता की जरूरत है जिनमें हर मानव अपनी जीवन प्रणाली व व्यवहार में बदलाव कर उस चुनौती का सामना करने के लिये कसर कस सके जो हमारे समाने पेश आ रही है”**
